

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण विभाग,,
तपोवन, रायपुर, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: ०१ मार्च, 2009

विषय: प्रेम विद्यालय राजकीय इण्टर कालेज, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) की ग्राम-कानिया, रामनगर (नैनीताल) में स्थित 2.019 हैक्टेअर भूमि स्टेडियम निर्माण हेतु युवा कल्याण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रेम विद्यालय राजकीय इण्टर कालेज, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) की ग्राम-कानिया, रामनगर (नैनीताल) में स्थित 2.019 हैक्टेअर भूमि को स्टेडियम निर्माण हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 260/वित्त अनुभाग-3/2002; दिनांक: 15 फरवरी, 2002 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन युवा कल्याण विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।
3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं।
4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि" हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं कराई जायेगी।
5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित "भूमि को कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो

क्रमशः.....2

या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

7. सीमा सड़क संगठन को अन्य सेवा विभागों की भांति वन भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

8. उत्तरांचल राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 261(1)/XXIV-3/09/02(66)2008; तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी,।
- 3- सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल-नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल, अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 8- जिला शिक्षा अधिकारी, -नैनीताल, अल्मोड़ा।
- 9- प्रधानाचार्य, प्रेम विद्यालय रा०इ०का० ताड़ीखेत (अल्मोड़ा)।
- 10- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

(६६)

(पी०एल०शाह)

उप सचिव।